E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2025; 7(3): 45-47
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 18-12-2024
Accepted: 22-01-2025

रीता सरकार
शोधार्थी, संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा, अम्बिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़ भारत

डॉ. जसिन्ता मिंज
शोध निर्देशक, राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़ भारत

Corresponding Author:
रीता सरकार
शोधार्थी, संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा, अम्बिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़ भारत

पंडो जनजाति में राजनीतिक जागरूकता का अध्ययन: सरगुजा जिले के संदर्भ में

रीता सरकार, जसिन्ता मिंज

DOI: https://doi.org/10.33545/26646021.2025.v7.i3a.462

सारांश
प्रकृति की अवशेष सम्पदा एवं सौन्दर्य का प्रतीक छत्तीसगढ राज्य आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। विशीष्ट लोक सस्कृति, लोककला, परम्पराओं पर्वत, नदियां सतत् प्रवाहिनी सरिताओं से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की अपनी पहचान है। पंडो जनजाति का निवास स्थान देखे तो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के बलरामपुर, सूरजपुर एवं सरगुजा है 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में इनकी जनसंख्या भारिया भूमिया, भूमिहर आदि के साथ की गई है। पिछले सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ में पंडो जनजाति की संख्या 31814 दर्शायी गई है। इस जनजाति की मुख्य जनसंख्या सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया आदि में अन्य लोगो की तुलना में आज भी अत्यंत पिछड़ी हुई है। समाज की अन्य लोगों की तुलना में इनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक राजनीतिक आदि विकास अत्यंत धीमी है इसलिए सरकार द्वारा इनकी जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के अनेक प्रयास किये जा रहे है ताकि समाज के अन्य लोगों के समान पंडो जनजाति का भी विकास हो सके। परन्तु आधुनिक युग के प्रवेश द्वारा पर खड़े होने के बाद भी समाज के अन्य लोगों की अपेक्षा ये जनजाति आज भी अत्यंत पिछड़ी हुई है।

कुटशब्द: पंडो जनजाति, राजनीतिक जागरूकता, सरगुजा, छत्तीसगढ, संस्कृति और संगठन

प्रस्तावना
छत्तीसगढ एक नवेदित राज्य है जो कि 01 नवम्बर 2000 को असित्व में आया विकास की असीम सम्भावनाओं के लिए यह जनजातीय राज्य बना, इस राज्य में कुल 31 जनजातियाँ निवासरत है। विकसीत जनजातियों में जहाँ उरांव और हलबा, जनजातियों है वही अल्प विकसित जनजातियों में नगेशिया पंडो और पहाड़ी कोरवा जनजातियाँ आती है। पंडो जनजाति न केवल अत्यंत पिछड़ी हुई है। अतः छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा भी पंडो जनजाति को विशेष रूप से पिछडी जनजाति घोषित किया गया है। पण्डों जनजाति को वर्ष 2002-2003 में विशेष पिछड़ी जनजाति समतुल्यन मानते हुए इनके लिए अलग से पण्डों विकास अभिकरण के द्वारा इन जनजातियों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने का भी प्रयास किया जा रहा है। यह जनजातियाँ मुख्य रूप से छ०ग० राज्य के सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, कोरिया, रायगढ़ एवं बिलासपुर जिले में निवास करती है।

उदेश्य
प्रस्तुत शोध पत्र के निम्न उदेश्य है:
1. पण्डों जनजातियों का सामान्य अध्ययन।
2. पण्डो जनजातियों का वर्तमान समय में राजनितिक जागरूकता का अध्ययन। .

विधितंत्र

पण्डो जनजातियों से संबंधित शोध ग्रंथों, शोध पत्रो का अध्ययन समाचार पत्रो का अध्ययन कर सही उदेश्य प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। साथ ही रिसर्च जनरल पुस्तक एवं वेबसाइट का भी उपयोग किया गया है।

राजनितिक जागरूगता

पण्डो जनजातियों का जीवन के क्रियाकलापों एवं गतिविधियों का अध्ययन उपरांत यह दृष्टिगत होता है कि जनजातिय समाज / समुदाय सदियों से ही समाज के अन्य लोगों से अलग अलग दुनिया में जीवन यापन करता रहा है जहाँ अशिक्षा बीमारी, गरीबी कुपोषण स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अध्ययन रूढिवादिता इत्यादि समस्या के कारण इनका जीवन स्तर अत्यंत पिछड़ा रहा है। यही कारण है कि सरकार इन पिछड़ी जनजातियों का पहचान करके इनके असित्व को बनाये रखने तथा समाज के मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में इनके विकास को सुनिश्चीत करने का प्रयास करता रहा है। अशिक्षा, अज्ञनिकता, रूढिवादिता तथा अंधविश्वास से ये जनजातिया घिरी हुई है। इसलिए वर्तमान समय में ये जनजातियाँ सरकार एवं राजनीतिक (प्रतिनीधि) के प्रति उदासीन है। तथा इसमें राजनीतिक पद जैसे सरपंच, सचीव, सरकार राज्य, ग्राम पंचायत जनप्रतिनीधि जनपद पंचायत सचीव एवं सरकार द्वारा चलाया जा रहे महत्वपुर्ण योजनाओं का लाभ पाण्डो जनजातियां नही ले पा रहे है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में राजनीतिक जागरूकता का अत्यंत कमी पाई गई है।

प्रस्तुत शोध पत्र के अध्ययन से प्राप्त तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि समाज के अन्य लोगों की तुलना में राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रति जागरूकता का बहुत ज्यादा अभाव है। सरकार द्वारा वर्तमान में भी योजनाओं का प्रचार प्रसार सामन्तय लेखन पंम्पलेट वितरण के द्वारा जागरूक किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। परन्तु प्रचार प्रसार के इन तरीको से जागरूक एवं समूह सरकारी योजनाओं एवं राजनीतिक जागरूकता का लाभ पाण्डो जनजाति नही उठा पा रहे है। प्रस्तुत शोध अध्ययन पत्र में यह जानने का प्रयास किया गया है कि पाण्डो गाँव में सरकार के विकास योजनाओं की स्थानिय स्तर पर जानने का प्रयास किया गया है। पाण्डो जनजाति की जागरूकता और विकास का अध्ययन करते है तो पता चलता है कि पाण्डो जनजाति को सरकार द्वारा 2002-2003 में विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में परिभाषित किया गया है। तब से योजनाएँ निरन्तर क्रियान्तित की जा रही है पाण्डो जनजातियों में राजनितिक जागरूकता का अध्ययन के उपरांत यह तथ्य उभरकर आता है।

पण्डो जनजातियों को राजनितिक व्यवस्थाओं राजनीतिक पद और राजनीतिक पद से मिलने वाले लाभ का बहुत ही कम जागरूकता हो पाई है क्यों की शिक्षा और राजनीति जागरूकता अभाव एवं भाषा संबंधी कठिनाईयों के कारण कई बार पाण्डो समुदायों के लोग चाहकर भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने नहीं आते इनसे वास्तविक हितग्राहियों का पहचान करने के लिए सरकार को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः पाण्डो में राजनीतिक जागरूकता का अध्ययन के पश्चात् यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि समाज के अन्य लोग एवं जनजातियों की अपेक्षा पाण्डो जनजाति में राजनिति के प्रति जागरूकता का अत्यंत अभाव पाया गया है। अतः हम कह सकते है कि आज पाण्डो जनजाति में राजनीतिक जागरूकता अत्यंत धीमा है। परन्तु यह भी सत्य है कि समय के साथ उनमें पंचायत पंच, सरपंच, सरकार, राज्य जनपद, अतः शासन की योजनाओं के प्रति जागरूकता बहुत धीमा है परन्तु निः सन्देह उनमें समय और परिस्थिति के अनुसार जागरूकता थोड़ा बहुत दिखाई पड़ता है परन्तु वर्तमान परिपेक्ष्य में यह राजनीतिक जागरूकता समाज के अन्य लोगों के अपेक्षा अत्यंत पीछे है। अतः इनके लिए सरकार के साथ-साथ समाज को भी सामने आना होगा जिससे इनका जीवन स्तर में राजनीतिक जागरूकता आ सके और सभी समाजो के साथ इनका समानता हो सके और ये जनजाति अपना पूर्ण विकास कर सके।

उपसंहार (निष्कर्ष)

पंडो जनजाति आधुनिक युग के प्रवेश द्वार पर होते हुए भी अशिक्षित एवं राजनीतिक चेतना से शुन्य है पंडो जनजाति के जीवन में सामन्य परिचय एवं राजनीतिक जागरूकता का अध्ययन करने के बाद यह तथ्य सामने आता है कि जीस गति से भारत में विकास हुआ है उस दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ के पण्डो जनजातिय में राजनीतिक जागरूकता का पूर्ण विकास नही हो पाया है अन्य जनजातियों के अपेक्षा ए जनजाति पिछड़ी हुई है परन्तु यह कहना उचीत होगा कि समय के साथ इनमें भी बदलाव आया है । परन्तु फिर भी सरकार के समक्ष इन्हे पूरी तरह राजनीतिक के प्रति जागरूकता बनाना एक चुनौती बनी हुई है। क्योंकि ए जनजातियां अशिक्षित, अंधविश्वास से घिरे होने के कारण राजनीतिक के प्रति जागरूकत नहीं हो पा रही है अतः इन्हे अधिक से अधिक शिक्षित बनाकर इनमें राजनितिक जागरूकता का विकास हो सकता है ।

संदर्भ ग्रंथ

1. रिजवी बी.आर हिल कोरवास ऑफ छत्तीसगढ़
2. श्रीवास्तव डॉ. आर.एन. जनजातिय संस्कृति
3. रूप नारायण मिश्र की दी अबुझमाडिया
4. डॉ. गोयल कंवर जनजाति संस्कृति और संगठन
5. नारायण अविनिंदर (1990) द कोरवा ट्राइब्स देयर सोसायटी एंड इकोनामिक्स (अमर प्रकाश दिल्ली)
6. तिवारी डॉ. शिवकुमार मध्यप्रदेश की जानकारिया"
7. श्यामा चरण दुबे "कमार जनजाति